

**MODERNISING COAL MINING**

♦626. SHRI KRTSHAN KANT : SHRI SYED AHMAD : SHRI KOTA PUNNAIAH : SHRI D. P. SINGH : SHRI CHANDRA SHEKHAR : DR. Z. A. AHMAD :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the progress so far made in modernising coal mining; and

(b) whether the private sector collieries are cooperating in this regard ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMARAMANGLAM): (a) and (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

**STATEMENT**

(a) and (b) So far as public sector is concerned, a majority of the coal mines under the National Coal Development Corporation Ltd. and the Singareni Collieries Company Ltd. are mechanised and have been modernised to the extent necessary under the prevailing conditions. Work of modernising the mines recently acquired by the Bharat Coking Coal Ltd. is still at the Planning stage.

In the private sector, coal industry spent about Rs. 14.17 crores out of the World Bank Loan of Rs. 16.67 crores during the Third Plan period, for importing coal mining machinery and equipment, etc. TISCO has launched a programme for re-structuring and modernising their coal mines producing coking coal needed for their steel plants. TISCO had taken up a programme of modernising and expansion of their two coal mines in Jharia with the help of World Bank Loan. This work has progressed well and one large coal washery has already been functioning treating coals from these two mines. Some private sector Companies have also modernised their mines but the majority of private sector Companies have continued with prevalent manual methods. The "Planning Group on the Fourth Five Year Plan Programme for Coal" did not envisage the necessity for additional investment for further mechanisation of the private sector non-coking coal mines (except equipment) during the IV Plan period as the demand

for coal, particularly non-coking coal, did not come up to the expected level.

**कोयले का वितरण**

\*627. श्री लाल आडवाणी :

श्री मानसिंह वर्मा :

श्री ना. कृ. शेजवलकर :

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

श्री डी. के. पटेल :

श्री रत्नलाल जैन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बिहार की कोयल खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिए जाने के पश्चात् कोयले के उत्पादन और विभिन्न इस्पात कारखानों को इसके वितरण तथा कर्मचारों के वेतन या भत्तों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**DISTRIBUTION OF COAL**

\*627. SHRI LAL K. ADVANI : SHRIMAN SINGH VARMA :

SHRI N. K. SHEJWALKAR :

SHRI JAGDISH PRASAD

MATHUR: SHRI D. K. PATEL : SHRI RATTAN LAL JAIN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state what steps are being taken by Government to improve the production and distribution of coal to various steel factories and with regard to pay and allowances of workers after the take over of coal mines in Bihar by Government ? 1

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : अपेक्षित जानकारी देनेवाला विवरण समा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

अगस्त 1972 में कोककारी कोयले के दुर्लभ संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा लौह और इस्पात उद्योग की इस प्रकार के कोयले के लिए बढ़ती हुई अपेक्षाओं की पूर्ति के प्रयोजनार्थ देश में 214 कोककारी कोयला खानों का उनके पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय

सरकार द्वारा इन खानों का प्रबन्ध अक्टूबर 1971 में ग्रहण किया गया था तथापि उनके पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके क्योंकि केन्द्रीय सरकार अगस्त 1972 में खानों के राष्ट्रीयकरण होने तक, प्राईवेट स्वामियों की ओर से अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। इस अवधि के दौरान इन खातों से प्राप्त उत्पादन की औसतन मात्रा लगभग 10.8 लाख टन प्रति माह के स्तर पर स्थिर रही। यह उस उत्पादन से कुछ ही अधिक है जो अक्टूबर, 1971 में प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व के दो महीनों के दौरान उत्पादन था। नए प्रबन्ध द्वारा प्रारम्भिक कठिनाइयों के सामना किए जाने पर भी यह सफलता प्राप्त हो सकी है। कोककारी कोयले के परिवहन और वितरण के लिए प्रक्षालन-शालाओं और इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त संख्या में बैगन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए गए थे और इस्पात संयंत्रों में इस प्रकार के कोयले की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रबन्ध ग्रहण की गई कोककर कोयला खानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की योजनाएं जो अनुध्याताधीन थीं अब अगस्त 1972 में खानों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कार्यान्वित की जा सकती हैं। जनवरी 1972 में भारत सरकार और पोलैंड जन गणतंत्र के मध्य हस्ताक्षरित सलेख के अन्तर्गत भारत कोककर कोयला लिमिटेड ने भारत की कोककर कोयला खानों की आयोजना, पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए पोलैंड के 'मैसर्स कोपैक्स' के साथ करार किया है। मैसर्स कोपैक्स विशेषज्ञीय सेवाएं प्रदान करेंगे और ऐसे पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की प्रथम प्रावस्थाओं को सम्मिलित कर साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग देंगे। इस प्रावस्था में वस्तु-सूची कार्य, विभिन्न खनन खण्डों के ग्रुप बनाने के प्रस्ताव, सीमाओं का पुनः सीमांकन, उत्पादन वृद्धि के लिए प्रौद्योगिक-आर्थिक साध्यता का मूल्यांकन और इन प्रत्येक खण्डों में विनिधान के लिए प्रावस्थिक विकास कार्यक्रम बनाना सम्मिलित है। सहयोग की अगली प्रावस्था में, जो बाद में तैयार की जायगी, चयनित खनन खण्डों के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करना सम्मिलित होगा। मैसर्स कोपैक्स भारतीय अभियंताओं के साथ सहयोग के लिए,

पोलैंड के विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करेंगे और वह पोलैंड में अनेक भारतीय अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करेंगे। इस बारे में भारतीय अभियंताओं का दल पहले ही पोलैंड गया है। वर्धित कोयला-उत्पादन के इस्पात संयंत्रों की वितरण के लिए, क्षमता विस्तार हेतु योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

जहां तक इन कोयला खानों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने के उपरान्त कोककर कोयला खानों में कर्मचारों के देतन और भत्तों का प्रश्न है मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों कार्यान्वित की गई हैं और प्रत्येक कर्मकार को श्रेणी I की न्यूनतम सुनिश्चित मजदूरी दी जा रही है और मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई दर पर जीविका-सूची की लागत की तुलना में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का संदाय किया जाता है। संविदा पर कार्यशील कर्मचारों को बड़ी संख्या में नियमित रोजगार दिए गए हैं।

[THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM):  
A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

#### STATEMENT

In August, 1972, 214 coking coal mines in the country have been nationalised with a view to reorganising and reconstructing them for the purpose of protecting and conserving the scarce resources of coking coal and promoting scientific development needed to meet the growing requirements for this type of coal by the iron and steel industry. Though the management of these mines was taken over by the Central Government in October, 1971, no effective steps for their reorganisation and reconstruction could be taken as the Central Government was acting as a Custodian on behalf of the private owners till the mines were nationalised in August, 1972. During this period, the production of coking coal from these mines has been more or less steady with an average monthly production of 1.08 million tonnes. This is slightly more than the rate of production which was prevailing for two months before the take-over in October, 1971. This is in spite of the teething troubles faced by

ff ] English translation.

the new management. Steps were also taken to make available an adequate number of wagons for the transport and distribution of the coking coal to the washeries and steel plants and there have been no complaints of any shortage of such coal at the steel plants.

2. The plans for the reorganisation and reconstruction of the taken over coking coal mines which have been under contemplation can now be implemented with the nationalisation of the mines in August, 1972. Under the protocol signed in January, 1972 between the Governments of India and the Polish People's Republic, Bhadrat Coking Coal limited has concluded an agreement with M/s. KOPEX, of Poland for planning, reorganisation and reconstruction of the coking coal mines in India. M/s. KOPEX will give expertise and renders services and collaborate in the preparation of feasibility reports covering the first phase of such reorganisation and reconstruction. This phase covers the inventory work, framing proposals for grouping into various mining blocks, redrawing of boundaries, assessing the techno-economic feasibility for expansion of production and working out a phased development programme for investment in each of these blocks. The next phase of collaboration which will be drawn up subsequently will cover the detailed project reports for selected mining blocks. M/s. KOPEX will depute Polish experts for collaboration with Indian Engineers and they will also undertake the training of a number of Indian engineers in Poland. A Team of Indian engineers is already in Poland in this connection. Plans are also being prepared for expanding the capacity for the distribution of the increased production of coal to the steel plants.

As regards pay and allowances of workers in the coking coal mines after the management of these mines was taken over by the Central Government, the recommendations of the Wage Board have been implemented and a minimum assured wage of Category I is being given to every worker and variable dearness allowance related to the cost of living index is being paid at the rate recommended by the Wage Board. A large number of contract workers have also been given regular employment.]

### इस्पात के कोटे का आवंटन

628. श्री मानसिंह वर्मा :

श्री ना. कृ. शेजवलकर :

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

श्री डी० के० पटेल :

श्री लाल आडवाणी :

श्री रत्तनलाल जैन :

सरदार कुमार सं० चं० आंग्रे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नट-बोल्ट आदि बनाने वाले उन कारखानों को जो छोटे कस्बों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थित हैं सामान्यतः आवेदन देने के कितने समय पश्चात् इस्पात का कोटा आवंटित कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात के शीघ्र आवंटन के लिये छोटे उद्योगों को इस्पात के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

### ALLOTMENT OF QUOTA OF STEEL

\*628. SHRI MAN SINGH VARMA :

SHRI N. K. SHEJWALKAR :

SHRI JAGDISH PRASAD

MATHUR: SHRID. K. PATEL:

SHRI LAL K. ADVANI : SHRI

RATTAN LAL JAIN : SHRI S.

C. ANGRE :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the length of time normally taken for the allotment of the quota of steel to the nut-bolt manufacturing small scale factories located in small towns and backward areas, after the submission of applications by them for the same;

(b) whether it is a fact that the process of allotment of steel to the small scale industries is being simplified for speedy allocation of steel; and

(c) if so the details thereof ? ]

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) आजकल